www.jagran.com
रजि. नं. एसएसपीओएसजेआई-291/15-17
वर्ष - 79
अंक -172
पृष्ठ - 16
मूल्य - 5 रुपये
झाँसी, शुक्रवार 5 फरवरी, 2021
नगर संस्करण

दैनिक जागरण

• दिल्ली • उत्तर प्रदेश • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखंड • बिहार • झारखंड • पंजाब • जम्मू कश्मीर • हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

राष्ट्रगीत के गायन में यूपी ने 2 घण्टे में ही चीन को पछाड़ा 12 ट्विटर ने हटाए कंगना के 2

बजट से कृषिवानिकी को मिलेगी संजीवनी

बहुउपयोगी साबित होगा वैज्ञानिक विकास मॉडल, अब तक कई तकनीक पर काम कर चुके हैं काफरी के वैज्ञानिक

झाँसी : वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों की उपज को और बेहतर बनाने के लिये राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्रों को अलग से बजट देने की घोषणा की गई है, जो बुन्देलखण्ड के कृषिवानिकी को संजीवनी देगी।

काफरी (केन्द्रीय कृषि वानिकी अनुसंन्धान संस्थान) के निदेशक डॉ. ए. अरुणाचलम ने बताया कि बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाया गया है। 5 साल में राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थान के लिए 50 हज़ार करोड़ की घोषणा की है, जो अन्य संस्थानों के साथ ही बुन्देलखण्ड के अनुसन्धान केन्द्र व उससे जुड़े किसानों के लिये उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में नव भारत के निर्माण के लिए विज्ञान के नेतृत्व वाले विकास मॉडल के लिए जो क़दम उठाया गया है, वह तन्त्र को और मजबूती प्रदान करेगा। विशेष रूप से उस समय, जब तीन कृषि बिलों को लागू करने के बाद बड़ी संख्या में किसान कृषि व्यापार और वाणिज्य, सम्वर्धन एवं सुविधा अधिनियम को लागू कर रहे हैं। वही, ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाकर खराब होने वाले 22 कृषि उत्पादों को भी बजट में शामिल किया गया है। यह योजना भी किसानों के लिये कारगर साबित होगी।

तीनों कृषि कानून वापस ले सरकारः प्रियंका वाड्रा पेज 09 | सेंसेक्स का नया रिक

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
शुक्रवार, 05 फरवरी 2021, कानपुर, पांच प्रदेश, 21 संस्करण, झांसी-ललितपुर संस्करण
www.livehindustan.com

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला है बजट

झांसी | निज संवाददाता

केंद्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान में गुरुवार केंद्रीय बजट पर संस्थान के निदेशक डॉ. अरुणाचलम ने कहा कि वित्तमंत्री द्वारा घोषित आवंटित बजट भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने को महत्वपूर्ण है। पिछले साल जहां इसमें रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई थी। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के कल्याण एवं ग्रामीणों, प्रवासी श्रमिकों एवं श्रमिकों और वित्तीय समावेशन को व्यापक स्तंभ के तहत 'एस्पिरेनल इण्डिया' के लिए समावेशी विकास को शामिल किया गया है।

रखी बात

- कृषि ऋण में 16.5 लाख करोड़ की वृद्धि, 5 हजार करोड़ सूक्ष्म सिंचाई निधियों को दोगुना
- कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के माध्यम से एपीएमसी की ढांचागत सुविधाओं को मजबूत किया

कृषि ऋण में 16.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी और अतिरिक्त रुपये 5 हजार करोड़ के साथ सूक्ष्म सिंचाई निधियों को दोगुना करना किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट दस्तावेज में जोर दिया गया है। 2013-14 के बाद सरकार द्वारा खरीद में निरंतर वृद्धि हो रही है। गेंहू तथा चावल खरीद में किसानों को भुगतान की गई राशि में क्रमशः 2013-14 से 2020-21 के दौरान 121 प्रतिशत और 170 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस अवधि में दालों के मामले में भुगतान की गई राशि में 40 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वहीं, कपास में किसानों को इस अवधि के दौरान लगभग 288 गुना की वृद्धि हुई। ग्रामीण ढांचागत संरचना विकास निधि को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ और ई-एनएएम के साथ एक हजार और मंडियों के एकीकरण को सुनिश्चित करना बजट की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं है। संचालन व आभार प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आरपी द्विवेदी ने व्यक्त किया।

झांसी, लखनऊ, आगरा, गुना, सतना, रीवा, भोपाल व ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

बुद्धिमान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता।
● चाणक्य

स्वदेश

● झांसी ● शुक्रवार, 05 फरवरी 2021, माघ कृष्णपक्ष-8 ● संवत् 2077,● युगाब्द 5122 ● वर्ष : 22 ● अंक : 215 ● मूल्य 3.00 रु. ● पृष्ठ 8

बजट भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने के लिए महत्वपूर्ण : डॉ. अरूणाचलम

झांसी। केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2021-22 पर संस्थान के निदेशक डॉ. ए. अरूणाचलम की अध्यक्षता में विचार मंथन किया गया। इस विचार मंथन के दौरान विश्लेषण में पाया गया कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित आर्वटित बजट भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले साल इसमें रिकॉर्ड कमी दर्ज की गयी थी। केन्द्रीय बजट 2021-22 में कृषि और उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के कल्याण एवं ग्रामीण भारतवासी, प्रवासी श्रमिको एवं श्रमिकों और वित्तीय समावेशन को व्यापक स्तंभ के तहत ''एस्पिरेशनल इंडिया के लिए समावेशी विकास'' को शामिल किया गया है। कृषि ऋण लक्ष्य में रू. 16.5 लाख करोड़ की बढ़ोत्तरी और अतिरिक्त रू. 5,000 करोड़ के साथ सूक्ष्म सिंचाई निधियों को दोगुना करना किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।इस बजट दस्तावेज में जोर दिया गया है कि 2013-14 के बाद से सरकार द्वारा खरीद में निरन्तर वृद्धि हो रही है और गेहूँ तथा चावल खरीद में किसानों को भुगतान की गयी राशि में क्रमशः 2013-14 से 2020-21 के दौरान 121: और 170: से अधिक की वृद्धि हुई है। इस अवधि में दालों के मामले में भुगतान की गयी राशि में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुयी है। वहीं कपास में किसानों को इस अवधि के दौरान लगभग 288 गुना की वृद्धि हुयी है। इसके अलावा कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के माध्यम से ए.पी.एम.सी. की ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने का प्रावधन सरकार की एक सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार डा. आर.पी. द्विवेदी, प्रधान वैज्ञानिक (कृषि प्रसार) ने व्यक्त किया।